

हीरापुरा पावर हाउस पर जबरन बस शिफ्टिंग के विरोध में प्रदेशव्यापी चक्का जाम

बस ऑपरेटर्स का आरोप - हीरापुरा में न तो पार्किंग, न वेटिंग एरिया और न ही पर्याप्त यात्री सुविधाएँ

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हीरापुरा बस स्टैंड से बस संचालन शुरू होने से पहले ही इसका विरोध शुरु हो गया और आल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन जयपुर की शनिवार को हड़ताल करने की घोषणा के बाद इन बसों का प्रदेशव्यापी चक्का जाम हो गया।

आल राजस्थान कां्ट्रेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हीरापुरा पावर हाउस (कमला नेहरू नगर) पर प्राइवेट बसों के जबरन स्थानांतरण के विरोध में राजस्थान स्तर पर चक्का जाम किया गया है। शर्मा ने बताया कि हीरापुरा पावर हाउस पर प्राइवेट स्लीपर बसों को जबरन स्थानांतरित करने के विरोध में प्रदेशभर की सभी बस यूनियनों के सहयोग से यह चक्का जाम किया गया।

उन्होंने बताया कि आरटीओ प्रशासन की ओर से एक अगस्त से सिंधी कैप बस स्टैंड से अजमेर रूट की सभी प्राइवेट और रोडवेज बसों

■ **हीरापुरा पावर हाउस पर प्राइवेट स्लीपर बसों को जबरन स्थानांतरित करने के विरोध में प्रदेशभर की सभी बस यूनियनों के सहयोग से यह चक्का जाम किया**

■ **परिवहन विभाग ने गैर कानूनी तरीके से खड़ी बसों का चालान कर हीरापुरा बस स्टैंड से इनका संचालन शुरू करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया**

को हीरापुरा शिफ्ट करने के आदेश के विरोध में एक हजार से ज्यादा स्लीपर और प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इन सभी संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे हीरापुरा से बसें नहीं चलाएंगे।

उन्होंने बताया कि इन बसों का संचालन हीरापुरा से नहीं करने पर परिवहन विभाग ने गैर कानूनी तरीके से खड़ी बसों का चालान कर हीरापुरा बस स्टैंड से इनका संचालन शुरू करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि करीब एक हजार बसों का चालान किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने बताया कि एक अगस्त तक का भी

कि सिंधी कैप से हीरापुरा की दूरी ज्यादा होने से यात्रियों को काफी असुविधा होगी। इसके अलावा हीरापुरा में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, वेटिंग एरिया, पार्किंग और यात्रियों के बैठने तक की सुविधा नहीं है वहीं रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं है। साथ ही ओला-उबर वाले एक हजार तक वसूली करेंगे। इतना तो बस किराया नहीं होता। वहीं किसी महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ और अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।

बस ऑपरेटर्स का कहना है कि परिवहन विभाग की यह कार्यवाही एकतरफा और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के की जा रही है। इस निर्णय में व्यवहारिकता और संवाद की पूरी तरह अनदेखी की गई है। निजी बसों की हड़ताल से आम यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा रविवार को होने वाली लाइब्रेरियन परीक्षा के 80 हजार अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है वहीं रोडवेज की मात्र 3050 बसें पूरे प्रदेश में चल रही हैं जो यात्री भार उठाने के लिए नाकाफी है।

जस्टिस शर्मा रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है।

वे अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। विधि विभाग ने सीजे केआर श्रीराम से परामर्श के बाद जस्टिस शर्मा का मनोनयन किया है।

सघन वृक्षारोपण एवं पौधों का निशुल्क वितरण किया

जयपुर। मालवीय नगर विकास महासमिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने तथा नागरिकों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने के लिए मालवीय नगर के विभिन्न सेक्टर पार्कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर 100 फल एवं छायादार पौधे लगाये गये तथा 200 से अधिक छोटे एवं बड़े पौधों का निशुल्क वितरण किया गया। महासमिति के अध्यक्ष आर भी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रेरणादायी नेतृत्व में संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते हुए प्रदेश ने 'हरियाली राजस्थान वृक्षारोपण महाभियान' के रूप में एक नयी हरित क्रांति का सूत्रपात किया है। कार्यक्रम के अतिथि महासमिति के मुख्य संयुक्त महेन्द्र कुमार हल्लिया एवं हरीश गुप्ता तथा क्षेत्रीय पार्षद राम प्रसाद शर्मा ने कम से कम एक पौधा प्रत्येक नागरिक को लगाने का संदेश दिया और वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने जनहित के इस कार्य को सराहनीय बताया।

सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न



मालवीय नगर के विभिन्न सेक्टर पार्कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर 100 फल एवं छायादार पौधे लगाये।

समितियों से पधारे हुए जन प्रतिनिधियों ने पौधे ले जाकर अपने अपने श्रेत्र में पौधारोपण कर इनकी देखभाल का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में राजेन्द्र कुमार गुप्ता, इन्द्र मोहन अग्रवाल, उमा गोतम, सुधीर गुप्ता, जुगल किशोर अग्रवाल ने स्लोगन, गाने एवं कविताओं के माध्यम से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को वर्षों, आक्ससीन एवं प्राणियों के जीवन के लिए उपयोगी बताया। महासमिति के महामंत्री सतीश चंद गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्द किशोर

स्वर्णकार, सचिव मुरारी लाल गुप्ता, अनिल सकसेना, एल एन कुमावत, गोतम शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया एवं पार्क में पौधारोपण के साथ पौधे वितरित भी किया।

इस अवसर पर देवेन्द्र खन्ना, मोहन लाल चावला, तेज करण पाराशर अरुण माथुर, आर सी कटारा, पी डी अरोड़ा, बाबू लाल गुप्ता, सुदर्शन सिंह शेखावत, रजनीश अग्रवाल, राजेश खंडेलवाल, सुरेन्द्र बिन्दल, युधिष्ठिर लाल शर्मा सतीश कुमार जैन, आर के व्यास एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

परिवहन निरीक्षक सुजानाराम चौधरी के 7 ठिकानों पर एसीबी का छापा

2.5 करोड़ (201 फीसदी) की संपत्ति अपनी वैध आय से अधिक अर्जित की

जयपुर/ जालौर। राजस्थान के सिरोही जिले में कार्यरत परिवहन निरीक्षक सुजानाराम चौधरी एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आज सुबह माउंट आबू, जोधपुर, भीनमाल और सिरोही के सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया।

एसीबी महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो को एक गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप था कि परिवहन निरीक्षक सुजानाराम चौधरी ने वाहन पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने, गुजरात बॉर्डर पर अवैध वसूली और वाहन निरीक्षण जैसी सेवाओं के बदले नियमित रूप से रिश्तत लेकर, अपनी और अपने परिजनों के नाम पर अपार चल-अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। इन संपत्तियों का मूल्य करोड़ों रुपये बताया गया।

■ **एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के तहत मामला दर्ज किया**

एसीबी ब्यूरो की इंटेलिजेंस शाखा ने जब इस शिकायत को गोपनीय तरीके से जांच की, तो चौधरी द्वारा माउंट आबू, जोधपुर, सिरोही और भीनमाल में रिहायशी व वायसायिक भूखंड, मकान और कोटियों की जानकारी सामने आई। इसके बाद तथ्यों का दस्तावेजी संकलन हुआ और जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने लगभग 2.5 करोड़ (201 फीसदी) की संपत्ति अपनी वैध आय से कहीं अधिक अर्जित की है। इसके आधार पर एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के तहत मामला दर्ज कर, जयपुर के उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन में, पाली-द्वितीय के

जयपुर। राजस्थान की पारंपरिक छतरियों, बावड़ियों, देवलियों और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज कर कानूनी संरक्षण देने की मांग को लेकर सेव ऑवर हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से उठाए गए प्रस्ताव को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। फाउंडेशन को इस मांग को लेकर 21 जुलाई को संस्था के चेयरमैन अरिहंत सिंह चरड़ास ने मंत्री शेखावत को पत्र भेजा था। इससे पूर्व 22 जून को हुई एक ऑनलाइन बैठक में संगठन के संयोजक हुकम सिंह पड़ासला ने यह मुद्दा मंत्री के समक्ष रखा था, जिस पर मंत्री शेखावत ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया था।

फाउंडेशन ने अपने पत्र में बताया कि संवत 2012 (वर्ष 1955) के भूमि सेटलमेंट में राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्थित अनेक धरोहरें-जैसे छतरियां, बावड़ियाँ, देवलियाँ आदि- सामान्य खातेदारी भूमि के अंतर्गत दर्ज हो गईं, जिससे उनके संरक्षण में

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को प्रतिष्ठित ‘संसद रत्न अवार्ड’ मिला

जयपुर। देश की संसदीय प्रणाली को सशक्त बनाने में विशिष्ट योगदान देने वाले राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को इस वर्ष का "संसद रत्न अवार्ड" प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें संसद में उनके उत्कृष्ट कार्य, जनहित के मुद्दों पर सक्रियता और विधायी योगदान के लिए दिया गया। "संसद रत्न अवार्ड" देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है।

यह पुरस्कार प्रतिष्ठित पार्लियामेंटी रिसर्च संस्था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के आशीर्वाद से प्रारंभ किया गया था। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने संसद के सत्रों में लगातार उपस्थिति, प्रभावशाली बहसों, प्रश्नों और जनहित



केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू (बीच में) ने मदन राठौड़ (बायें) को सम्मानित किया ।

याचिकाओं के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक एवं विकासात्मक मुद्दों को संसद में उठाया, जिससे आम जन की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच मिला। पुरस्कार वितरण समारोह का

आयोजन नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में आयोजित किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। इसमें देश भर के वरिष्ठ सांसद, नीति निर्माता, सामाजिक

पूर्व सैनिकों तक पहुंचेगी निशुल्क विधिक सहायता

जयपुर। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से पूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों और उनके परिजनों को निशुल्क व सुलभ विधिक सहायता मुहैया कराने के लिए वीर परिवार सहायता योजना-2025 की शुरुआत की गई है। योजना को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से से राज्य सैनिक बोर्ड, जयपुर में भी विधिक सेवा क्लिनिक का शुभारंभ किया गया।

प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया की योजना के तहत प्राधिकरण की ओर से प्रेश्र के प्रत्येक जिले में जिला सैनिक बोर्ड के परिसर में विशेष विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। इसके माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। इस मौके पर प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण सैन्य कर्मियों और उनके परिवार के निरंतर सहयोगी रहेगा।

तीज के अवसर पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया

जयपुर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 27 व 28 जुलाई को शाम 6 बजे तीज माता की सवारी निकाली जायेगी। जिसके चलते 27 व 28 जुल को यातायात व्यवस्था निम्न प्रकार से रहेगी।

तीज माता की सवारी के दौरान सामान्य यातायात पुराना पुलिस मुख्यालय के पीछे व जलेब चौक में से होकर सिटी पैलेस की तरफ नहीं आ सकेगा। तीज माता की सवारी के दौरान सामान्य यातायात आतिश मार्केट व सार्दुल सिंह की नाल की तरफ से किसी भी प्रकार के वाहन सिटी पैलेस की तरफ नहीं आ जा सकेगें, तीज माता की सवारी के दौरान सामान्य यातायात चीनी की बुर्ज की तरफ से किसी भी प्रकार का ट्रैफिक आतिश बाजार तथा सिटी पैलेस की तरफ नहीं आ सकेगा।

तीज माता की सवारी के दौरान रामनिवास बाग चौराहा, न्यूगेट चौराहा से चौड़ा रास्ता में जाने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों से संचालित किया जायेगा, तीज

आयोग ने स्कूल की छ्त गिरने की घटना पर लिया संज्ञान

जयपुर । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने झालावाड़ जिले के पीपलौदी गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को शनिवार को नोटिस जारी कर तीन दिन में पूरे मामले की जांच एवं प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने प्रेस तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशित समाचार, जिसमें राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलौदी सरकारी स्कूल के भवन का एक हिस्सा गिरने से सात बच्चों की मृत्यु होने एवं नौ बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने तथा कई बच्चों के मलबे में दबकर धायल होने से संबन्धित समाचार का स्वतः संज्ञान लिया है। इसमें कई बच्चे काथित रूप से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हैं।

आयोग ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में नोटिस जारी कर तीन दिन में पूरे मामले की जांच एवं प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

डोटासरा ने सांसदों एवं विधायकों से सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए आगे आने की अपील की

जयपुर । राजस्थान में झालावाड़ जिले में पीपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिर जाने की हृदयविदारक घटना के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने प्रदेश के सभी सांसदों एवं विधायकों से राजनीति से ऊपर उठकर जनता के प्रति जनप्रतिनिधि की जवाबदेही का दायित्व निभाते हुए जीर्ण-शीर्ण सरकारी स्कूलों के भवन एवं अन्य जन उपयोगी भवन की मरम्मत एवं उन्हें ठीक कराने के लिए आगे आने की अपील की है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। डोटासरा ने शनिवार को इस संबंध में एक पत्र लिखकर प्रदेश के सांसद एवं विधायक जनप्रतिनिधियों से यह अपील की। उन्होंने कहा "यह वक्त पक्ष-विपक्ष का नहीं, जवाबदेही का है। आइए.. हम सब राजनीति से ऊपर उठकर जनता के प्रति जनप्रतिनिधि की जवाबदेही का दायित्व निभाएं और संवेदना से संकल्प का प्रण दोहराएं ताकि फिर किसी स्कूल से चीखें न आएँ, फिर किसी मां की गोद सूनी न

हो, फिर किसी परिवार का चिराग ना बुझे, फिर झालावाड़ जैसे हार्दसों की पुनरावृत्ति ना हो" उन्होंने अपील करते हुए कहा कि समस्त सांसद एवं विधायक जनप्रतिनिधि अपने संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों में संपद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएड) से जर्जर स्कूल के भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं जन उपयोगी भवनों की प्राथमिकता से मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यकता अनुसार राशि स्वीकृत कराने के लिए आगे आना चाहिए।

उन्होंने पत्र में लिखा कि पीपलौदी गांव की घटना हृदयविदारक है और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सब लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों एवं कस्बों में स्थित शासकीय विद्यालय भवन, आंगनवाड़ी केंद्र तथा अन्य जनउपयोगी भवन जो वर्तमान में अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

रिटायर महिला व्याख्याता को बकाया भुगतान के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ की पीजी कॉलेज से रिटायर महिला व्याख्याता को उसका जनवरी 2016 से जुलाई 2019 तक का बकाया वेतन और समस्त सेवानिवृत्त परिलाभ तीन माह में अदा करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश कुष्णा जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि एक बार जब राज्य सरकार ने कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया तो उस संस्था के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही मानी जाएगी। यदि राज्य सरकार यह मानती है कि कॉलेज का अधिग्रहण साल 2020 में हुआ था तब भी 70 फीसदी देयदारी राज्य सरकार की बनती है और वह शेष तीन फीसदी कॉलेज की प्रबंध समिति से वसूल सकती है।

याचिका में अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हनुमानगढ़ के अनुदानित कॉलेज में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के तौर पर साल 1983 में नियुक्त हुई थी। उस समय वह अनुदानित कॉलेज ही था। पुलिस की शुरुआती जाँच में यह बात सामने आई कि यह मादक पदार्थ एक बड़े तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है और इसमें सागर धाकड़ की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। धाकड़ पर आरोप था



एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने डोडा चूरा के मामले से जुड़े 25 हजार के इनामी तस्कर सागर धाकड़ को गिरफ्तार किया।

कि वह नागौर जिले में कई स्थानीय तस्करी को बेगू थाना क्षेत्र से डोडा चूरा की सप्लाई करता था।

एडीजी एमएन ने बताया कि सागर धाकड़ बेहद शातिर अपराधी था। वह अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखता था और घर के बजाय अधिकतर दूर खेतों में ही सोता था, ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सके। एजीटीएफ की टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत

शर्मा के सुपरविजन में पिछले करीब दो महीने से सागर की तलाश में जुटी थी।

पुलिस निरीक्षक राम सिंह नाथावल के नेतृत्व में गठित टीम सदस्य कांस्टेबल गोपाल धावाड़ व विजय सिंह को सटीक सूचना मिली कि सागर धाकड़ भीलवाड़ा के मांडलगढ़ इलाके में लाड़पुरा चौराहे के पास अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा है। सूचना पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की।